www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523
Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2023 Page No. : 93-99
AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

ग्रामीण क्षेत्रों में नकद रहित लेन–देन के चलन का अध्ययन

सुनील कुमार
I

सार :–

डिजिटलीकरण दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है और इसने व्यापार परिदृश्य को बदल दिया है। बाजार संक्रमण के चरण में हैं, किराना स्टोर, हाइपर मार्केट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और प्लास्टिक कार्ड का उपयोग, ऑनलाइन शॉपिंग और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आदि। आरबीआई और सरकार नकदी के उपयोग को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करने के कई प्रयास कर रहे हैं।

डिजिटल लेनदेन बेहतर पारदर्शिता, मापनीयता और जवाबदेही लाते हैं। पिछले एक दशक में विमुद्रीकरण ने नकद रहित लेनदेन में तेजी से वृद्धि देखी है। अन्य संस्थानों के साथ समन्वय में, दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार कैश–आधारित से नकद रहित सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जो एक भविष्यवादी, नकद रहित समाज के विचार की ओर ले जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय लेन–देन के लिए प्रौद्योगिकी का हालिया विकास नीति निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों के लिए वर्तमान संस्थागत व्यवस्थाओं की उपयुक्तता और वित्तीय स्थिरता, दक्षता और मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता की गारंटी के लिए उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में चुनौती पेश करता है।

भुगतान प्रणाली के विभिन्न रूप अस्तित्व में रहे हैं जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली और वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याओं के कारण विभिन्न प्रकार के धन की शुरुआत हुई। डिजिटलाइजेशन ने आर्थिक नीतियों में कई उल्लेखनीय बदलाव लाए हैं और नकद रहित अर्थव्यवस्था इस डिजिटल पुश की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। देश में चलाए गए विमुद्रीकरण के कदम से लोगों में नकद रहित समाज की ओर एक कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा पैदा हुई।

भूमिका :–

तकनीकी नवाचार के उद्भव के कारण वित्तीय सेवा उद्योग अचानक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बैंकिंग क्षेत्र पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस नए फिनटेक युग में भारत में बैंक पारंपरिक से सुविधाजनक बैंकिंग दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं। इस नकद रहित सोसाइटी को शुरू करने और इसकी ओर बढ़ने में काफी समय लगा। प्रारंभ में, यह एक बड़ी सफलता नहीं थी लेकिन अंततः यह सामने आई है। अब, यह उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ विश्वव्यापी इंटरनेट उपलब्धता के कारण प्रगति कर रहा है। भुगतान और निपटान सुविधाओं की इन नई किस्मों को प्रोत्साहित करने के आरबीआई के

प्रयास का उद्देश्य कम नकद समाज के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नया कदम अधिक व्यापारियों को डिजिटल धन स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा।

नकद रहित सोसाइटी और नकद रहित लेनदेन इकोनॉमी शब्द डिजिटल रूप से लेनदेन करने के बजाय नकद लेनदेन और निपटान को कम करने का संकेत देते हैं। नकद रहित लेनदेन इकोनॉमी का मतलब कैश की कमी नहीं है, बल्कि यह डिजिटल तरीके से लेनदेन करने वाले लोगों की संस्कृति को दर्शाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में, पैसा इलेक्ट्रॉनिक रूप से चलता है। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ–साथ डिजिटल भुगतान संस्कृति का प्रसार आवश्यक है।

नकद रहित इकोनॉमी ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें वास्तविक नकदी के बदले लेन–देन महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया जाता है और नकद आधारित लेनदेन की मात्रा न्यूनतम रखी जाती है। सरकार का उद्देश्य सभी लोगों के बीच और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नकद रहित लेनदेन के तरीकों को बढ़ावा देना है।

डिजिटल इंडिया भारत को एक डिजिटल सशक्त समाज और एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। आरबीआई और भारत सरकार प्रीपेड उपकरणों और सभी कार्डों सहित डिजिटल भुगतान उपकरणों या विधियों को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था में भौतिक नकदी के उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहे हैं।

इन्हें प्रोत्साहित करने के आरबीआई के प्रयास, भुगतान और निपटान सुविधाओं की नई तकनीकों का उद्देश्य 'कम नकदी' समाज के उद्देश्य को प्राप्त करना है। वहीं, नकद रहित सोसाइटी और नकद रहित लेनदेन इकोनॉमी शब्द डिजिटल रूप से लेनदेन करने के बजाय नकद लेनदेन और निपटान को कम करने के लिए एक ही बात का संकेत देते हैं।

नकद रहित लेनदेन इकोनॉमी का मतलब कैश मनी की कमी नहीं है, बल्कि यह डिजिटल तरीके से लेनदेन को निपटाने वाले लोगों की संस्कृति को दर्शाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में पैसा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रवाहित होता है। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ–साथ डिजिटल लेन–देन प्रणाली का प्रसार आवश्यक है।

तकनीकी अवसंरचना के निरंतर स्तर और नीतिगत परिवर्तनों के कारण भुगतान के तरीकों की संख्या में वृद्धि हुई है। नकद रहित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य है जहां नकदी का भौतिक प्रवाह नहीं होगा। सभी भुगतान आभासी दुनिया में किए और प्राप्त किए जाएंगे। विमुद्रीकरण के बाद नकद रहित अर्थव्यवस्था लोकप्रिय हुई जहां प्लास्टिक मनी का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। अध्ययन का उद्देश्य नकद रहित अर्थव्यवस्था के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता के स्तर का अध्ययन करना है।

नकद रहित इकोनॉमी उस शब्द को संदर्भित करती है जहां करेंसी नोटों और सिक्कों के भौतिक प्रवाह को पैसे के डिजिटल प्रवाह से बदल दिया जाता है, जिसमें प्लास्टिक मनी, डिजिटल साधनों का उपयोग और शुद्ध लेनदेन शामिल हैं। इस तरह के प्रतिस्थापन का अर्थ करेंसी नोटों को तत्काल हटाना नहीं है, बल्कि एक उचित प्रक्रिया का पालन करके धीरे–धीरे और धीरे–धीरे कागजी मुद्रा को बाहर करना है।

साहित्य की समीक्षा :–

श्री तावड़े (2017) भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था का भविष्य और दायरा। यह पेपर भविष्य के

रुझानों और भारतीय आर्थिक परिदृश्य में नकद रहित होने के प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है। अध्ययन किए जाने के बाद यह देखा गया कि भारत सरकार को भारत को डिजिटल बनाने के लिए कई और कदमों पर विचार करना चाहिए। और भुगतान के तरीकों को और अधिक सुरक्षित और जोखिम मुक्त बनाया जाना चाहिए।

अरोड़ा (2017), जेनेसिस ऑफ नकद रहित सोसाइटीरू प्लास्टिक मनी के प्रति बढ़ती स्वीकार्यता पर एक अध्ययन। इस पेपर का उद्देश्य हाल के वर्षों में प्लास्टिक कार्ड की स्वीकार्यता में तेजी से वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों का अध्ययन करना है। अध्ययन किए जाने के बाद यह देखा गया कि प्लास्टिक कार्ड का उपयोग किशोरों के बीच बहुत गर्व की बात है और इसे सुरक्षित और किसी भी धोखाधड़ी से मुक्त माना जाता है।

डॉ. गुजराती (2017), फेसलेस, पेपरलेस, नकद रहित इकोनॉमी की ओर भारत का मार्च। पेपर का उद्देश्य नकद रहित अर्थव्यवस्था, इसके लाभों, चुनौतियों और नकद रहित अर्थव्यवस्था की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जागरूकता की भावना पैदा करना है। किए गए शोध के बाद यह देखा गया कि नकद रहित अर्थव्यवस्था विभिन्न लाभों के साथ आती है लेकिन इसके साथ बहुत अधिक चुनौतियां भी लाती हैं।

डॉ. आशा शर्मा (2017), पोटेंशियल फॉर नकद रहित इकोनॉमी इन इंडिया। यह अध्ययन भारत के नकद रहित अर्थव्यवस्था बनने की संभावना, नकद रहित अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का पता लगाने के लिए किया गया था। अध्ययन से पता चलता है कि नकद रहित भारत का एक महत्वपूर्ण दायरा है क्योंकि हम आज जिन विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें समाप्त कर सकते हैं लेकिन हमें उन चुनौतियों और समस्याओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नकद रहित अर्थव्यवस्था लाएगी।

रजनी (2018), नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन पर एक अध्ययन। अध्ययन का उद्देश्य नकद रहित अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति में व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन करना है। किए गए अध्ययन के बाद यह देखा गया कि बहुत से लोग पहले ही नकद रहित राष्ट्र की ओर बढ़ चुके हैं या आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत को नकद रहित बनने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

खुराना (2015), नकद रहित इंडिया का सपना : लाभ और चुनौतियां। यह पेपर उन लाभों और चुनौतियों का अध्ययन करता है जिनका भारत को सामना करना पड़ सकता है यदि यह नकद रहित राष्ट्र बन जाता है। यह डिजिटल इंडिया के अर्थ और नकद रहित इंडिया के सपने को हासिल करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का आकलन करने में भी मदद करता है। अध्ययन के बाद सरकार ने डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए कितना भी कुछ कर लिया हो, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है।

जिंदप्पा (2017), भारत में आम आदमी पर नकदी रहित अर्थव्यवस्था का प्रभाव। अध्ययन भारत में रहने वाले एक आम आदमी पर नकद रहित होने के प्रभाव और नकद रहित होने से संबंधित चुनौतियों पर केंद्रित है। अध्ययन से पता चलता है कि भारत कभी भी पूरी तरह से नकद रहित अर्थव्यवस्था में नहीं बदल सकता क्योंकि नकदी का प्रभुत्व रहा है और हमेशा रहेगा। नकद रहित होना समाज के एक बहुत छोटे वर्ग के लिए

ही संभव होगा, पूरे देश के लिए नहीं।

खन्ना (2017), नकद रहित पेमेंट : ए बिहेवियरल चेंज टू एन इकोनॉमिक ग्रोथ। पेपर का उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि भारतीय आर्थिक परिदृश्य में एक व्यवहारिक परिवर्तन ने आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित किया। किए गए अध्ययन के बाद यह देखा गया कि इस तरह के बदलाव के लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार थे क्योंकि लोग इस तरह के बदलाव को अपनाकर विभिन्न लाभ और अवसर पा रहे थे।

शंकर (2018), नकद रहित इकॉनमी/लेनदेन। पेपर नकद रहित अर्थव्यवस्था के प्रभाव और भारत में इसके महत्व को समझने पर केंद्रित था। किए गए शोध के बाद यह देखा गया कि भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था की शुरुआत से वित्तीय क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और भारत में भुगतान प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में नकद रहित लेन–देन का चलन :–

बैंकिंग के माध्यम से धन के संचलन पर पारदर्शिता, दक्षता लाने और काले धन पर लगाम लगाने के लिए अर्थव्यवस्था में नकद रहित लेनदेन की आवश्यकता सामने आती है। भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रही है।

पारंपरिक भुगतान विधियों का डिजिटलीकरण बैंकिंग उद्योगों, इंटरनेट सेवाओं और मोबाइल उद्योगों का एक क्रांतिकारी विकास है, जो लोगों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह दुनिया भर में नई तकनीकों और विकास को स्थापित करने का अवसर पैदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप देश का आर्थिक विकास होता है।

डिजिटल भुगतान नकद रहित अर्थव्यवस्था का दिल है। डिजिटल भुगतान लेन–देन का एक तरीका है जिसमें विभिन्न प्रकार के डिजिटल मोड का उपयोग करके भुगतान किया जाता है। डिजिटल भुगतान में लेन–देन ऑनलाइन पूरा होता है। डिजिटल भुगतान तब होता है जब उत्पादों को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग से खरीदा जाता है। इस प्रकार की भुगतान पद्धति में नकद या सुविधाजनक तरीकों का कोई उपयोग नहीं है। इसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान भी कहा जाता है।

डिजिटल भुगतान बिना ज्यादा समय लिए दुनिया में कहीं भी अपने उपयोगकर्ताओं के व्यापारिक लेनदेन के लिए आर्थिक स्वतंत्रता पैदा करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता लोगों को दुनिया भर में व्यापार करने की अनुमति देती है। वे दुनिया भर में कुछ ही घंटों में सुरक्षित और सुरक्षित लेनदेन के साथ हस्तांतरण या भुगतान स्वीकार करके विश्व स्तर पर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं और यह भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करता है।

नकद रहित प्रणाली के विकास से समानांतर काली अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगता है जो मुख्य रूप से नकदी के आधार पर चलती है। नकद रहित लेनदेन ट्रैक करने योग्य और भौतिक लेनदेन की तुलना में अधिक पारदर्शी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन हमेशा भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए एक डिजिटल प्रूफ फायदेमंद छोड़ देते हैं और इसलिए सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और अनुपालन बनाते हैं। नकद रहित सिस्टम बिना ज्यादा समय लिए स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन–देन के निपटान को गति देता है।

भारत में नकद रहित प्रणाली का एक और बड़ा लाभ यह है कि पिछले कुछ वर्षों में कर चोरी में भारी

गिरावट आई है क्योंकि डिजिटल माध्यम से किए गए भुगतान ट्रैक करने के लिए उपयोगी होते हैं और इस तरह सरकारी एजेंसियों के लिए खर्च का ट्रैक रखना और अधिक लाना आसान हो जाता है। कर दायरे में आने वाले लोग जो पहले बड़ी आय होने के बावजूद कर का भुगतान नहीं कर रहे थे।

भारत एक ग्रामीण बहुल देश है जहाँ निरक्षरता दर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी अधिक नहीं है। भारत में डिजिटल साक्षरता सिर्फ 10 प्रतिशत है। देश की आधी से ज्यादा आबादी अभी भी कंप्यूटर का उपयोग करना नहीं जानती है। भारत में अभी भी कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं जहां हाई स्पीड नेटवर्क तक पहुंच बहुत मुश्किल है। इसके अलावा, देश में हर कोई इसकी उच्च लागत के कारण इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रहा है। हम डिजिटल साक्षरता के अभाव में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक पारंपरिक शाखा आधारित मॉडल से आभासी रूप से मौजूद नकद रहित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।

भारत में नकद रहित नीति के विकास में एक और बड़ी चुनौती साइबर सुरक्षा के मुद्दे हैं। डिजिटल लेन—देन कई मुद्दों का सामना करता है जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी का जोखिम, गोपनीय जानकारी का रिसाव, साइबर अपराध, मैलवेयर और वायरस के हमले आदि। भारत जैसे देशों में डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने के लिए यह सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है जहां डिजिटल साक्षरता बहुत कम है।

पूर्वोक्त परिवर्तनों के समानांतर भुगतान का तरीका बदल गया है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड व्यापक हो गए हैं और नकदी को निचोड़ना शुरू कर दिया है, जबकि संपर्क रहित प्रौद्योगिकियों के उद्भव ने इन भुगतान साधनों के उपयोग को और बढ़ा दिया है। स्मार्ट फोन ने भुगतान में भी क्रांति ला दी।

नकद रहित समाज उस समय से अस्तित्व में है जब मानव समाज अस्तित्व में आया, वस्तु विनिमय और विनिमय के अन्य तरीकों के आधार पर, लेकिन वास्तविक नकदी रहित समाज को एक ऐसे समाज की ओर बढ़ने और इसके निहितार्थों के अर्थ में समझा जाना चाहिए जहां नकद को इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

सरकारें डिजिटल सेवाओं की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करती हैं क्योंकि वे इसे मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी को संबोधित करने और वित्तीय सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में देखती हैं। दूसरों का तर्क है कि डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं को लूटने या पैसे खोने से बचाता है, साथ ही उन्हें लगातार वॉलेट ले जाने की परेशानी से बचाता है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष बताते हैं कि डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग करने के मामले में भारत अभी भी दुनिया के अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत खराब है। जैसा कि कई देश पहले से ही अपने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के साथ बदल चुके हैं, भारत अपने शुरुआती चरण में है और सभी आबादी मुख्य रूप से उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता, जागरूकता की कमी और वित्तीय लेनदेन के ज्ञान की कमी के कारण कागजी नकद आधारित लेनदेन पर निर्भर है। कार्ड भुगतान और गैर परिचालन बैंक खातों पर शुल्क।

सरकार को डिजिटल लेनदेन भुगतान पर अतिरिक्त लाभ प्रदान करना चाहिए और बैंक खातों में नकद बचत पर अतिरिक्त प्रोत्साहन या ब्याज दर की पेशकश करनी चाहिए। साथ ही डिजिटल लेन—देन के शुल्कों में कमी या डिजिटल बैंकिंग पर पूरी तरह से कुछ शुरुआती वर्षों के लिए छूट की पेशकश की जानी चाहिए जो भारत में भुगतान के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिक सहायक हो सकती है।

भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में कुछ चुनौतियाँ हैं। भारत में सभी देशों के क्षेत्र में छोटे

खुदरा विक्रेताओं का एक विस्तृत नेटवर्क है और उनमें से अधिकांश के पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर उपभोक्ताओं की धारणा और विश्वास है कि नकद मदद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान बुनियादी ढांचे में निवेश करने और डिजिटल रूप से भुगतान करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। आप बेहतर बातचीत करते हैं। नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर न बढ़ने में भी निहित स्वार्थ है, और कार्ड और नकद का उपयोग करने वाले अधिकांश लोग डरते हैं कि कार्ड का उपयोग करने पर उनसे अधिक शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा, ज्ञान की कमी या नई तकनीकों और वित्तीय साक्षरता के अपर्याप्त ज्ञान के कारण, क्रेडिट कार्ड का उपयोग न करने वाले लोगों को क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लाभों के बारे में पता नहीं होता है। भारतीय बैंक निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी किए गए डिजिटल वॉलेट को संबंधित बैंकों की वेबसाइटों पर उपयोग करने के लिए इसे समस्या बना रहे हैं।

नकद रहित लेन–देन का मुख्य अवसर यह है कि सभी आर्थिक लेन–देन का उचित रिकॉर्ड रखना संभव है। काला बाजार और भूमिगत अर्थव्यवस्थाएं आम तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देने में प्लास्टिक मनी की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि नकदी मनी लॉन्ड्रिंग का एक साधन है और आतंकवाद के वित्तपोषण में लेनदेन प्राथमिक तरीका है। इसलिए इस तरह की गतिविधियों को काफी हद तक कम करने में नकद रहित इकॉनमी फायदेमंद है। इस नकद रहित लेनदेन से केंद्र सरकार को भी लाभ होता है क्योंकि यह पैसे की आपूर्ति पर केंद्रीय नियंत्रण की अनुमति देता है और नकद रहित अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए आयकर की निगरानी करना आसान होता है। नकद रहित लेन–देन नकारात्मक वैश्विक मुद्रास्फीति और मात्रात्मक सहजता के संदर्भ में सहायक होते हैं।

नकद रहित अर्थव्यवस्था में लोग विश्व स्तर पर अपना लेन–देन आसानी से कर सकते हैं। हितग्राहियों के खातों में बड़ी पारदर्शिता के साथ सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाया जा सकता है। नकद लेन–देन डिजिटल होने से लेन–देन की लागत भी कम हो जाती है। भौतिक मुद्रा पर अक्सर तम्बाकू, सिगरेट आदि के गंदे निशान पाए जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया, कीटाणु, विषाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं, जो बीमारी के कारणों में से एक बन जाते हैं। डिजिटलाइजेशन से इस तरह के खतरों को खत्म किया जा सकता है।

सरकार के इस कदम के प्रति देश के लोगों की प्रतिक्रिया के रूप में नकद रहित भारत का भविष्य काफी आशाजनक दिखता है और इसके प्रति समर्थन एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार का कदम सफल होने की संभावना है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि नकद रहित लेनदेन अर्थव्यवस्था भारत सरकार के अच्छे और मजबूत फैसलों में से एक है। बहुत से लोग नकद रहित लेनदेन प्रणाली की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। यह आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्री आदि जैसी अर्थव्यवस्था में प्रमुख अवैध या अनैतिक गतिविधियों से लड़ने में मदद करता है। इसलिए, ऑनलाइन शरारतों से बचाने के लिए इंटरनेट सुरक्षा को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। नकद रहित लेनदेन के आवेदन में ग्राहकों और छोटे खुदरा विक्रेताओं को उच्च स्तर के जोखिम और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कम साक्षरता दर है।

निष्कर्ष :–

नकद रहित लेन–देन एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्तियों को किसी भी मूर्त वस्तु के आदान–प्रदान के बिना

सामान या सेवाएं खरीदने की अनुमति देती है। डिजिटल भुगतान के अधिक उपयोग से काफी बचत होगी क्योंकि इससे भारत में नकदी की लागत कम करने में मदद मिलेगी। नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास से पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और आर्थिक विकास में आसानी होगी।

भारत के लिए सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान अवसंरचना का वातावरण बनाने की दिशा में रोडमैप में लोगों के वित्तीय समावेशन और विकास की सीढ़ी को अत्यधिक बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, जिस पर सरकार को सख्ती से काम करना चाहिए। नकद रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और विकसित करने की दिशा में।

डिजिटल भुगतान चैनलों के उचित तरीकों को अपनाकर भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था हासिल की जा सकती है, जिसके लिए नई सुरक्षित और सुरक्षित वित्तीय नीतियों, केंद्रीकृत प्रशासनिक नियंत्रण, बैंकरों, सरकारी एजेंसियों और अन्य निजी सेवा पर नियमित मौद्रिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ाने के लिए, यह सुरक्षित और सुरक्षित सेवाओं की मांग करता है जैसे भुगतान का तत्काल प्रमाणीकरण, उनके खातों का स्पष्ट विवरण, कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, पैसे पर पूर्ण नियंत्रण, लेनदेन की प्रक्रिया को पूरा करके छोटा करना अनिवार्य जानकारी। ग्रामीण क्षेत्रों का परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

संदर्भ :–

1. श्री प्रदीप एच. तावड़े (2017) भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था का भविष्य और दायरा।
2. ढांडा और अरोड़ा (2017) जेनेसिस ऑफ नकद रहित सोसाइटी प्लास्टिक मनी के प्रति बढ़ती स्वीकार्यता पर एक अध्ययन।
3. डॉ. रश्मी गुजराती (2017) फेसलेस, पेपरलेस, नकद रहित इकोनॉमी की ओर भारत का मार्च।
4. डॉ. आशा शर्मा (2017) पोटेंशियल फॉर नकद रहित इकोनॉमी इन इंडिया।
5. डोमिनिक, सरन्या और रजनी (2018) नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन पर एक अध्ययन।
6. श्री भरत खुराना (2015) नकद रहित इंडिया का सपना लाभ और चुनौतियां।
7. मेत्री और जिंदप्पा (2017) भारत में आम आदमी पर नकद रहित अर्थव्यवस्था का प्रभाव।
8. कुमारी और खन्ना (2017) नकद रहित भुगतान आर्थिक विकास के लिए एक व्यवहारिक परिवर्तन।
9. फेलिक्स, रेबेका और इगबिनोबा (2015) नाइजीरियाई अर्थव्यवस्था में ई–बैंकिंग और नकद रहित समाज के प्रभाव का मूल्यांकन।
10. कौसल्या और शंकर (2018) नकद रहित अर्थव्यवस्था लेन–देन।
11. कोकिला और उषादेवी (2017) नकद रहित लेनदेन पर उपभोक्ता व्यवहार पर एक अध्ययन।
12. थॉमस और कृष्णमूर्ति (2017) नकद रहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था–एक सपना या वास्तविकता।
13. श्रीकला के.के. (2017) नकद रहित लेन–देन कर्नाटक के कोडागु जिले के विशेष संदर्भ में अवसर और चुनौतियां।
14. शेंडगे, शेलार और कापसे (2017) भारत में नकद रहित लेनदेन का प्रभाव और महत्व।
15. गर्ग और पांचाल (2017) भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था के परिचय पर अध्ययन 2016 लाभ और चुनौती।